KSK/RPM/4.00/3B

SHRI T.K. RANGARAJAN (CONTD.): The Government says that it is 'Ease of Doing Business', but it is not able to provide employment, and the world record says that your rank on Global Hunger Index is going down. More people suffered from hunger during your regime. Country's advancement, returns on investment and prosperity must be measured not by making loud noise, but by productivity and employment generation. I can give you only one example. Our Finance Minister, in his last Budget Speech, said that he had allotted a lot of money for MNREGA, but the total workdays came to 23,515. In Tamil Nadu alone, the percentage of days for which the jobs were generated is 44 in 2015-16, 46 in 2016-17 and 7 in 2017-18. This is the case of Tamil Nadu. AIADMK Members are here. They must know that. You have generated 1.15 lakhs jobs in 2014-15. It is not my figure. It is your figure. In 2015-16, you have generated 2.3 lakh jobs. And, in 2016-17, there is a marginal increase. I agree with that. These figures are taken along with the figures of jobless and underemployment. Thousands of employment opportunities generated have been completely wiped off.

Sir, the Prime Minister had said that two crore jobs would be created every year. The President of the ruling party, Shri Amit Shah, is here. The

Prime Minister talked about creating two crore jobs every year. Even if you take all the three years of your regime put together, you are not able to reach even 50 lakhs. It is negative. Similarly, agrarian crisis is the worst crisis which we have suffered. Still, we are suffering. There is no help from the Centre. You say that agrarian subject is a State Subject. You are not prepared to implement Swaminathan's Report, which you had promised in your electoral rallies. Such policies have adversely affected the livelihood of the people. The only gainers are the corporates. The only people, who did not criticise you on demonetization and GST, are the corporates. All other people are suffering like anything. Sixty-five per cent wealth has gone to only one per cent people. Sixty-five per cent of the country's wealth is controlled by only one per cent of the people. In fact, looting the majority and benefiting the handful has become the order of the day. That is what you promote in your neo liberal policy. (Time bell)

Sir, up to neck, the policy of corruption is there. They can't say that the Government is not corrupt. It is corrupt. Wherever you go, you will see this. I have spoken to some people also. Sir, the Government policy has adversely affected the economy and it is actually a policy of corruption in pursuance of the so-called crusade against corruption. The entire policy

regime must be reversed to save the people and save the country, and provide employment for lakhs and lakhs of educated and rural masses.

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री वीर सिंह जी। आपके बोलने के लिए तीन मिनट का समय है।

श्री वीर सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरे बोलने के लिए दो मिनट और बढ़ा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : वीर सिंह जी, मुझे विश्वास है कि आप तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लेंगे।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारे देश में बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे-धीरे यह समस्या बहुत बड़ा रूप धारण करती चली जा रही है। हमारे देश में वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है।

(3 सी/पीएसवी पर जारी)

PSV-SK/3C/4.05

श्री वीर सिंह (क्रमागत): यह सोचने का विषय है। महोदय, लम्बे अरसे तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही। वह भी नारा लगाती रही कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। गरीबों की गरीबी तो दूर नहीं हुई, लेकिन इस देश का पूँजीपति-उद्योगपति मालामाल होता चला गया तथा गरीब और गरीब होता चला गया।

महोदय, आज बड़ा सोचने का विषय है। हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर कम्पनीज़ हैं, वे बेची जा रही हैं। बड़े-बड़े सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। आज इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। परम पूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण दिया था, आज धीरे-धीरे करके उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आज केन्द्र की सरकार पब्लिक सेक्टर कम्पनीज़ को उद्योगपतियों को बेच रही है। बड़े-बड़े सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। तो जो सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे, जब वे रिटायर होंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी की नौकरी नहीं लगेगी। रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा। इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका आरक्षण जान-बूझ कर खत्म किया जा रहा है। हमारी नेता, बहन मायावती जी ने माँग की थी कि हम प्राइवेट सेक्टर के विरोध में नहीं हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में दो, किन्तु जैसे पहले से आरक्षण चला आ रहा है, उन विभागों में, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद भी उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो आज धीरे-धीरे करके जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, स्लो पॉइज़न की तरह, उसको रोका जाना चाहिए, उस ओर ध्यान देना चाहिए। आज उनको और बेरोज़गार किया जा रहा है।

महोदय, 2014 के लोक सभा के आम चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि देश में जितने भी शिक्षित बेरोज़गार हैं, पढ़े-लिखे युवा हैं, मेरी सरकार बनवा दो, हमारी सरकार बनवा दो, जब हम सरकार में आ जायेंगे, तो हम एक साल में

2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, पाँच साल में 10 करोड़ नौकरियाँ देंगे। सभी बेरोज़गार, जितने भी शिक्षित हैं, सबकी नौकरी लग जायेगी। सभी बेरोज़गार, जितने भी शिक्षित थे, उन्होंने आँख मींच कर सपोर्ट किया। आज सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल होने जा रहे हैं। अब तक 7 करोड़ नौकरियाँ लग जानी चाहिए थीं, किन्तु वह वायदा पूरा नहीं हुआ है। आज पूरे देश का शिक्षित बेरोज़गार अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इससे बेरोज़गारी और बढ़ी है।

आज बड़े दुख का विषय है कि पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी का बैकलॉग पूरा नहीं है। मैं बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ...(समय की घंटी)... जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने सभी विभागों में बैकलॉग की सूची तैयार की कि कितना बैकलॉग है और उसको भरने का पूरा काम किया। आज मैं दावे से कह रहा हूँ कि पूरे देश में, सरकारी नौकरियों में यदि एससी, एसटी, ओबीसी का बैकलॉग कहीं पूरा है, तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के माध्यम से पूरा हुआ है। यह प्रयास सभी प्रदेशों की सरकारों को करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकारें हैं, केन्द्र में सरकार है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी के हितैषी हैं, तो सबसे पहले सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को पूरा कीजिए और बेरोज़गारी को दूर कीजिए, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): धन्यवाद।

श्री वीर सिंहः आज पूरे देश की महानगरपालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगरपालिकाओं को सरकार से विकास के लिए जो धन जाता है, उसमें से धीरे-धीरे करके ठेकेदारों को दिया जा रहा है। ठेकेदारी व्यवस्था की जा रही है। पॉलिसी चेंज की जा रही है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वीर सिंह जी ...(व्यवधान)... आपका समय पूरा हो गया है। श्री प्रफुल्ल पटेल। ...(व्यवधान)...

श्री वीर सिंहः नौकरियों का अवसर खत्म किया जा रहा है। ...(व्यवधान)... सिर्फ उद्योगपतियों को, बड़े-बड़े ठेकेदारों को वह दिया जा रहा है। उससे बेरोज़गारों की संख्या और बढ़ रही है। यह सोचने का विषय है कि एक तरफ तो हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो नगरपालिकाओं में, महानगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आज रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, ठेकेदारों को रोज़गार सौंपा जा रहा है। एक ठेकेदार, जो पूँजीपति होता है, उद्योगपति होता है, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार गरीबों के लिए हित का काम नहीं करती है, छोटे व्यापारियों के हित का काम नहीं करती है, यह किसानों के हित का काम नहीं करती है, यह सिर्फ उद्योगपतियों और पूँजीपतियों के हित का काम करती है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वीर सिंह जी ...(व्यवधान)... आप खत्म कीजिए। ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

श्री वीर सिंहः *

(**श्री उपसभापति पीठासीन हुए**)

श्री उपसभापति : बस। Time over. ..(Interruptions).. Time over. ..(Interruptions).. Please stop. ..(Interruptions).. Nothing will go on record. Now, Shri Praful Patel. ..(Interruptions)..

श्री वीर सिंह: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ..(Interruptions)..

श्री वीर सिंह: * (समाप्त)

(3डी/वीएनके-वाईएसआर पर आगे)

---

* Not recorded.

YSR-VNK/4.10/3D

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Praful Patel, do you want to speak? Prafulji, I am sorry, the time allocated to you is very limited. Three minutes is the limit. But you can take five minutes. I am helpless.

SHRI PRAFUL PATEL (MAHARASHTRA): Sir, it is an important discussion. If I have to finish it in three or four minutes...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am helpless. You change the rules. Otherwise, in the morning discussion, you should take more time.

SHRI PRAFUL PATEL: Shall I give up my turn? It does not matter. ...(Interruptions)... I am saying that I will not exceed more than three or four minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much.

SHRI PRAFUL PATEL: I will make a few points and stop there.

उपसभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और समय सीमित है, इसलिए मैं यहां पर कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा या ज्यादा प्वाइंट्स भी नहीं बताऊंगा। सर, हमारे देश में जब economy की बात होती है, तो वित्त मंत्री जी भी जानते हैं कि रोज सवेरे अख़बार पढ़िए या टीवी में देखिए, तो शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स होता है, उसके आधार पर हमारा मूड भी, जैसे economy है, उसी की बदौलत ऊपर-नीचे हो रहा है, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। शेयर बाजार की वजह से तो अभी ऐसा लगता है कि सब बहुत ही बढ़िया है, देश में कोई प्रश्न है नहीं, विकास और सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आज भी हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार सक्रिय तरीके से उनके बारे में भी सोचेगी, गंभीर तरीके से सोचेगी, ऐसी हम सबको आशा है।

जब से यह सरकार आई, तब से सरकार के लिए एक बहुत अनुकूल परिस्थिति रही है और वह है तेल के दाम की। Oil prices के मामले में आपके लिए यह लगातार चौथा साल है, जब कि अनुकूल वातावरण रहा है। इसका बहुत फायदा इस सरकार को निश्चित रूप से मिला है। हमारे समय में कम से कम डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपए की

ऐसी राशि थी, जो सरकार को या तो ऑयल कंपनीज़ को उनका लॉसेज़ को पूरा करने के लिए देनी पड़ती थी या बहुत सारी अन्य सब्सिडीज़ देनी पड़ती थीं, जिनकी वजह से सामान्य लोगों पर बोझ कम पड़ता था। लेकिन यह अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी आज एक बात निश्चित है कि हमारे बहुत सारे economy के पैरामीटर्स पर उसका विपरीत प्रभाव अभी भी दिख रहा है। खास करके जहां जॉब क्रिएशन की बात होती है, नए रोजगार पैदा करने की बात कई लोगों ने कही है, उस बात से हम सब सहमत हैं कि ग्रोथ एक ओर होती है, जीडीपी के आंकड़ों की हम लोग चर्चा जरूर करते हैं। But I am sure, hon. Finance Minister, you are seized of the issue. We have to see more job creation. Ultimately, that is one area which, I think, is a national concern. I am not making it into a partisan concern. It has to be dealt with very effectively. Rural economy में जॉब्ज़ की कटौती हो रही है। बड़े शहरों कोई नए जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। नए उद्योग-धंधे जिस तरह से, जिस तेजी के साथ आने चाहिए, उसमें हम लोगों के लिए यह जरूर एक सोच का विषय अभी भी बना है।

Make in India एक अच्छा initiative जरूर है, लेकिन Make in India के साथ Ease of Doing Business की भी जो बात हम करते हैं, उसमें हम लोग कितना सफल हुए हैं, इसके बारे में आज भी सोचना होगा। Ease of Doing Business केवल दिल्ली के गलियारों में, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हम लोग कहेंगे, तो उतने से नहीं होने वाला है। उसको हमें राज्य सरकारों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं Ease of Doing Business की बात कर रहा हूँ। It doesn't limit itself to Delhi. It

doesn't limit itself to important offices of Delhi. It also goes down to the States which are the real implementing agencies. राज्यों के तहत कई संस्थानों के माध्यम से Ease of Doing Business आज भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसकी वजह से, आज जॉब क्रिएशन की भी जब बात करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक्सपोर्ट पर आपकी नजर जरूर होगी। हमारे देश में जितनी मात्रा में एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही है। Amount of exports is not growing at the rate with which we would be comfortable. In spite of India being one of the cheapest areas in the world to source its goods from, we are still not able to break into a higher export zone. This is something which worries us. We need to look at it very objectively. (Contd. by VKK/3E)

-YSR/VKK-NKR/3E/4.15

SHRI PRAFUL PATEL (CONTD.): One more important thing I feel is, farming sector पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी इस बारे में चिन्ता जरूर होगी कि farming sector is not growing. In fact, it is now showing some decline or the growth, which is coming, is coming from a few areas of the farming sector. There is not a universal growth in the farming sector. I think that is an area of great concern for all of us. In rural economy also, सरकार की जितनी स्कीमें थीं, ग्रामीण economy में जितना पैसा जाता था,

आपने बहुत सी योजनाओं में कटौती कर दी, सर्व-शिक्षा अभियान से लेकर, IRDP और आवास योजना जैसी कई योजनाओं में आपने कमी कर दी, जिसके कारण ग्रामीण economy में जो राशि पहले जाती थी, उसमें कमी आई है। GST के आंकड़ों में भी आप देख लीजिए, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं और आपके पास अधिकृत आंकड़े ज्यादा आते होंगे, लेकिन शुरू में जो आंकड़े आए, उसके बाद कुछ-न-कुछ GST के आंकड़ो में गिरावट आने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या कोई economic उसकी वजह है? Is the economy under stress or are there other reasons? I am sure you are in a better position to answer as and when you get the opportunity.

Sir, finally, when we talk in great context with China, we must see the amount of imbalance that is now taking place between our two countries. While they export phenomenal amounts of goods to India, they are hardly absorbing any imports from India. Therefore, every year, the trade gap is increasing and widening to a great extent. And I think it should be a matter of great concern to all of us. On the one side, we want 'Make in India' and we want to grow our economy; on the other side, we are helping another country to grow its economy at our cost. I think somewhere down the line — I am not saying that this is an issue of today — this has to be dealt with very effectively. Ultimately, this will affect job creation and growth of our

economy. I know I have very limited time. Therefore, I have made all my points in brief. Thank you very much.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I am really sorry. I want to allow more time but I am helpless. That is the point. Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in this Short Duration Discussion on the state of the economy. Sir, if we go by the major events that have taken place in the country in the last one year, we will be able to have a better view of how the state of the economy is.

Sir, to start with, we may look at the effects of demonetisation. In the initial stages, it affected the informal sector. Small-scale businesses were affected. Some unemployment did take place. But, the better side of it was that the basic aim of demonetisation to curb black-money and unearth black-money has resulted in giving good results. Some fat accounts have come to notice. Numerous numbers of accounts are under scrutiny and they are under Income-Tax lens. So, that will serve as a deterrent to the people who evaded tax by which the country had to regress. I think this step would be a progressive step in time to come.

Then, another major thing was GST — the greatest indirect tax reform that India has ever seen. In the initial stages, that too had adverse effect as far as business community was concerned. But, with the successive role of GST Council and GST Network arrangement, the shortcomings, which were there in the initial stages, are being removed. The way the accrual is coming and the revenue is increasing, I think, GST has proved to be the step which was aimed at progressive economy of the country and that is helping it. Earlier, the loopholes which were available and the evasion of tax which was taking place as far as GST indirect tax was concerned, those are plugged. So, transparency has come and GST is showing its worth that it was much needed. The only thing is the rationalisation which is still required to be done in the area. I think the Finance Ministry and the Government will take due care of that.

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI TIRUCHI SIVA, in the Chair)

So, in the last couple of years, as far as successive monsoon failures are concerned, the agricultural economy has taken a very bad hit. The economy has got a bad hit and in the agricultural sector, a large section of the rural community dependent on it had to give up.

(Contd. by RL/3F)

-VKK/RL-DS/4.20/3F

SHRI ANIL DESAI (CONTD.): And, they had to move out of that. So, to rehabilitate them, to get them into the mainstream and to provide them the jobs likewise and create opportunities for them, that is a daunting task in front of the Government. But, I think, the Government is doing its bit so that even that is taken care of in the times to come.

As for foreign investment on the domestic front, that is investment within India, that is also being taken care of by the Government by giving them good platform like 'Make in India' and even 'Ease of Doing Business'. A lot of hiccups are there and a lot of hurdles are there but they are also being taken care of. As far as my State Maharashtra is concerned, like 'Make in India', we have 'Make in Maharashtra', where good results are forthcoming, good opportunities are being created for the industries, be it on the small scale, medium scale or the large industries, and even the foreign investment is really coming to the State of Maharashtra, and by the kind of opportunities which are being given and the support being given from the Central Ministry, Maharashtra will be the number one progressive State in times to come.

Sir, with the re-capitalization programme declared by the Government of India, banks would be replete with funds and credit lines, which were not showing good results, and, in times to come, banks would be flush with funds. They would be able to lend to the investors, to the industrialists and things should improve on that front also. So, all that will matter as far as job creation is concerned. We need to see that though public sector is on a decline as far as job opportunities are concerned but the private sector and manufacturing sector—these are the two sectors and the services sector is also there, which give maximum employment to the people of our country—are taken care of by the Government. A lot of schemes are being evolved and a lot of new opportunities are being created so that the employment opportunity would be good enough.

Sir, the unorganized sector, which is of concern and that should be the area where the Government has to pay more attention because the exploitation of labour is taking place there, no permanent jobs are given in any sector, be it in the small or medium scale or even large industries or even public sector too. They have resorted to employing people on contract basis. So, there is depletion; if by merits you go, then, jobs are not given to the qualified candidates. They have to remain on contract basis.

The Government has to create opportunities and channelize the things in the informal sector. The informal sector, in the sense, unorganized sector, that should be given more thrust so that all-round development would come and economy reaches on the right track and will have a push forward. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for the opportunity. Sir, I would like to dwell upon three important issues. First one is, overall job creation that has come down in the recent past. Second is, participation of women labour force is going down. That is the second issue. And, the third issue is decreasing unemployment among the educated people. These are the three issues on which I would like to concentrate and I wish that the Government of India would address these two issues.

Sir, according to the employment and unemployment survey conducted by the National Sample Survey Organization, during the last five years, employment generation was to the extent of thirty-six lakhs thirty thousand jobs have been created. It means, on an average, per year about 6 lakh jobs. On the other hand, the total employment that has been

generated between December, 2014 and December, 2015, it is only 1.35 lakhs. So, against the average of 6 lakhs per year, in the last year between December, 2014 and December, 2015, the job creation was only 1.35 lakhs. It means that there is a significant fall in job creation.

(CONTD. BY KR/3G)

KR/MCM/3G/4.25

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): I request the hon. Finance Minister to address this issue. Sir, on a perusal of annual data as confirmed by the Labour Bureau which has analysed it, the number of people in the workforce to the total workforce in the economy declined by 1.6 crore between March, 2014 and July, 2015. This is one issue.

The second issue is, the National Sample Survey Office report shows that labour force participation rate of women in rural India has slipped dramatically in the last 20 years. This is the second issue.

The third issue is, we often think that more education will lead to more employment. But, in fact, the situation is not so in India. In fact, it is counter-intuitive. I am not saying counter-productive but counter-intuitive.

The Ministry of Labour and Employment, in reply to a question in the Lok Sabha on 1st January, 2018, said that the unemployment rate for persons

aged between 18 and 29; who are not literate is 2.2 per cent; and graduate and above, it is 18.4 per cent. When we refer particularly to the IT sector, which forms one of the biggest sectors for educated youth, it is also facing trouble today. More than one lakh IT workers in India are expected to lose jobs in 2017 and 2018 due to increased automation of IT services. I request the hon. Finance Minister or the concerned Minister and the Government of India to address these three issues in the interest of the people of the country. Thank you very much.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Mr. Vijayasai Reddy. Very good, well in time. Next, Mr. Ajay Sancheti.

SHRI AJAY SANCHETI (MAHARASHTRA): Mr. Vice-Chairman, Sir, the subject of today's discussion is the current status of economy, job creation and rising unemployment.

सर, 2014 में जब मोदी सरकार ने जिम्मा संभाला, तब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं थी। इण्डस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति भी ठीक नहीं थी, एफ0डी0आई0 का फ्लो बहुत कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति गंभीर थी। देश के बैंकों की स्थिति विशेष कर एन0पी0ए0 के कारण, चिंताजनक थी। इन सभी स्थितियों से मार्ग निकालना, उद्योगों को बढ़ाना, फाइनेंशियल डिस्पिलेन लाना, अर्थव्यवस्था को

मजबूत बनाना, हर हाथ को काम की स्थिति को क्रिएट करना, यह एक चैलेंजिंग टास्क है। सभी सरकारें देशहित में अनेक निर्णय लेती हैं। लेकिन जिस स्पीड से जो काम होना चाहिए, जब वह नहीं होता तो अनेक कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सर, मोदी सरकार इन कठोर निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। आज हमारे देश की स्थिति जब सरकार ने काम संभाला था, उस समय से कई गुना परिस्थितयों में अंतर हो चुका है। इस सरकार ने न सिर्फ पुराने इश्यूज़ को स्ट्रीमलाइन किया, साथ ही साथ विकास कार्यों का एजेंडा भी तेजी से आगे बढ़ाया। सर, मैं अब कुछ चीजों का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन, Ease of doing business, Make in India को बढ़ावा, डिफेंस सैक्टर में इंडियन कम्पनीज़ का पार्टिसिपेशन, स्टार्ट-अप कम्पनीज़ का प्रमोशन, मुद्रा लोन का डिस्ट्रिब्यूशन, इंक्रीज़ इन स्कॉलरशिप, एफोर्डेबल हाउसिंग के प्लान को बनाना तथा 2022 तक हर व्यक्ति को घर मिले इसकी योजना तैयार करना, क्वालिटी इन सर्विसेज़ को रीज़नेबल कॉस्ट पर कैसे मिले, उसकी चिंता करना, ऑल्टरनेट फ्यूअल को इंक्रीज़ करना, ताकि डीजल और पेट्रोल का आयात हम कम कर सकें और सोशल और इकोनॉमिक सैक्टर्स में सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, जिन स्कीम्स से लाभ हो, उनको बढ़ावा देना। सर, ये जो सभी चीजें हैं, इस सरकार ने इतने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स शुरू किए। सर, Demonetization और जी0एस0टी0, ये दोनों ही इस सरकार के द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णय थे। सर, इनीशियली कोई भी जब एक बड़ा कदम उठाया जाता है, तो उसकी तकलीफ सभी को होती है।

(3H/GS पर जारी)

KS-GS/3H/4.30

श्री अजय संचेती (क्रमागत) : सरकार इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ऐसा नहीं है कि आज किसी निर्णय को लागू किया, तो कल से उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे, लेकिन जब दूरगामी परिणामों की चिंता की जाती है। It is like if you have to go for a good dinner in a restaurant, तो जब आदमी अच्छी जगह रेस्टोरेंट में जाता है, अच्छा खाना वहां उसको मिलने वाला है, एनवायर्नमेंट अच्छा है, तो आदमी सोचता है कि मैं सुबह खाना कम खाऊं, थोड़ा-सा लाइट भी खाऊं, ताकि मुझे शाम को बहुत अच्छे से खाना खाने को मिले, उसकी पसंद का खाना खाने को मिले। सर, जीएसटी, डिमॉनेटाइज़ेशन इसी प्रकार के दोनों निर्णय थे। तकलीफ इनीशियली हुई, लेकिन आज उसके जो परिणाम हैं, उनको हम सब देख रहे हैं।

Sir, initial problems are faced by people and the Government, but for a better and a bright future, it is a very, very small cost. Now, we are seeing the fruits of it. Few of them to name are; FOREX reserves have increased; stock exchanges are seeing substantial increase day after day; fiscal deficit is reduced than the Budgeted; substantial growth is seen in core sectors like steel and cement; Mudra loan is a huge success for small and poor; FDI is increasing day-in-and-day-out; country's rating has moved ahead.

सर, एक्सपोर्टर्स खुश हैं, इम्पोर्ट कम हो गया है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचने लगा है। सर, कोई माने या न माने पुराने legacy issues को पटरी पर लाते हुए, नये काम को बढ़ाना और सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, मल्टिपल बढ़ाना एक चैलेंजिंग काम होता है। इससे देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है कि यह ज्यादा हुआ या कम हुआ। सर, मेरा कहना यह है कि जितने भी आंकड़े हैं, इनकी फिगर्स में जाने के बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल कम्पनियों का काम बढ़ा है, ultimately, that is also an employment. पहले मैं किसी के यहां काम करता था, आज मुझे बैंक लोन देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं खुद का काम करने के लिए तैयार हो गया हूं और कर भी रहा हूं। इससे भी इस देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। आने वाले समय में यह और तेज़ी से बढ़ेगा। यह सिर्फ मेरा ही नहीं, यह जनता का भी विश्वास है और आने वाले समय में इन सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की दृष्टि से देश के रिज़र्व को बढ़ाने की दृष्टि से जितने भी काम किए जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष भी इसमें constructive साथ देगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Ajay. Now, Shri Shadi Lal Batra.

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चर्चा का विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इसको कितना महत्व देती है, सरकार

के पास एक आर्ट है मार्केटिंग और मार्केटिंग में सरकार सोचेगी कि किस प्वाइंट को किस तरह से उठाना है, कौन से आंकड़ों की ओर जाना है, क्या बात करनी है। जब चार साल पहले चुनाव थे..

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chaior)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Batraji, your time-limit is four minutes. आप बोलिए।

श्री शादी लाल बत्रा : जब चार साल पहले चुनाव हो रहे थे, तो कितने वायदे किए गए थे, क्या कुछ नहीं कहा गया था, उनकी मार्केटिंग करके चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कौन-सा वायदा पूरा किया, क्या किया? आज सबसे पहले मैं खेती-बाड़ी के बारे में कहूंगा। हमारे देश की 70 परसेंट आबादी गांव में रहती है और वह खेती पर निर्भर करती है। उस खेती के लिए सरकार ने क्या किया, उस खेती की ग्रोथ कितनी बढ़ गई या कम हो गई और कितने फार्मर्स ने सुसाइड किया या नहीं किया, थोड़ा उसको देखेंगे। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है और मैं इस पर आधारित हूं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट नवम्बर, 2017 में आई है, उसमें कहा गया है कि demonetization के बाद, GST के बाद एग्रीकल्चर में क्या हुआ? सरकार द्वारा लागू demonetization के बाद किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं था, कैशलेस सोसायटी हो गई थी, उनके पास कैश नहीं था, किसान के पास फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए पैसा नहीं था और फर्टिलाइज़र न खरीदने का एक ही कारण था कि किसान के पास पैसा नहीं था।

(HMS/3J पर जारी)

RSS-HMS/3J&K/4.35-4.40

श्री शादी लाल बत्रा (क्रमागत) : नीति आयोग की रिपोर्ट की relevant lines हैं, Fertilizer off-take during the current rabi season, till 21st December 2016, was lower than the fertilizer off take in the corresponding period during 2014-15 and 2015-16 by 7.47 per cent and 7.0 per cent. उसके बाद जब फर्टिलाइज़र नहीं खरीदा गया तो एक पॉइंट के पीछे 1.25 लाख करोड़ का नुकसान होता है। उन्होंने लिखा है कि One per cent decrease in fertilizer use can result in a 0.1 per cent decrease in agricultural GDP and 0.14 per cent decrease in crop output. As the rabi season constitutes half of the annual agricultural output, this shortfall in fertilizer utilization can result in a 1.05 per cent decline in crop output and 0.75 per cent decline in agricultural output. और फिर the total loss of the crop sector was estimated to be 0.26 per cent at this stage. The report also states that demonetization was responsible for creating a glut in the market in December 2016. उसके बाद कितना नुकसान हो गया? देश के 52 परसेंट लोग जो खेती-बाड़ी पर निर्भर करते थे, वहां कमी आ गयी। वे jobless हो गए और वे नीचे 30 परसेंट पर आ गए। तो जो इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ जॉब्ज़ सालाना देंगे, वे नहीं मिले। पहले दो साल तो इन्होंने "मनरेगा" का बजट कम कर दिया था। इस साल बढ़ाया है और यह माना है कि इस प्रोग्राम से जॉब्ज़ मिलते हैं, लेकिन

रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। उस का लाभ गांव तक नहीं पहुंचा और आज गांव वाले निराश हैं कि हमारा आगे क्या होगा।

मैं तो इस सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप marketing अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उन गरीबों की ओर भी देखो, जो गांवों में रहते हैं। यह ठीक है कि यह सरकार अमीरों की है और इसे अमीरों की चिंता है, इसे तो कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों की चिंता है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो कर रहे हैं, वह नज़र आ रहा है, लेकिन आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है और मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? I told you that your time is four minutes.

श्री शादी लाल बत्रा : सर, आर0बी0आई0 ने नवम्बर, 2017 में एक सर्वे किया था और उसकी एक रिपोर्ट आयी थी, जिस के अनुसार आज सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 45 परसेंट लोग ऐसे हैं, जो सोचते हैं कि यह सरकार हमारा कुछ भला कर सकती है, लेकिन 55 परसेंट यह कह रहे हैं कि यह सरकार भला नहीं कर सकती। इस सरकार के पास न कोई लक्ष्य है और न कोई सोच है।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? I am helpless. Okay. All right. Thank you very much. Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Thank you, Sir. My previous speakers dealt with several aspects of our economy, and made several suggestions. Sir, the economy is in a very bad shape. After demonetization, after GST roll out, many economists have admitted that it will lead to economic slow-down. Now, the industrial sector, manufacturing sector, small and medium sector, they are all in crisis. Agriculture is passing through unprecedented distress. Economy is in bad shape. Unemployment and under-employment are the most burning problems which the youth of this country are facing. Their future is so bleak and uncertain. In such a situation, what should we do? What the Government of the day can do because the Government of the day has made several promises. For that matter, Mr. Prime Minister made several promises of creating two crore jobs, of bringing back black money, and so many other things. I am not getting into those issues; I am not getting into polemics. But, I would like to raise certain fundamental issues. It is time, whether this Government, or, those who were in the previous Government, should realise the economic reforms, which all of us, or, all the countries adopted, had led to unprecedented inequalities. Now, everybody quotes Thomas Piketty to prove the point how unprecedented the inequality has grown in every country, and it includes India also. Sir, in such a situation

we should look back and do some serious introspection. Now, we are in 2018. In 2008, there was a global financial crisis, melt down. At that time, I remember, Dr. Manmohan Singh, who is sitting here, was the Prime Minister, and Mr. Pranab Mukherji was the Finance Minister. India was not that way affected by that crisis, and both of them claimed that it was because our fundamentals were quite strong, and we could withstand that crisis. Even at that time, we asked, what were those fundamentals? If you claim that those fundamentals were strong, what were those fundamentals, if not, the public sector undertakings; if not, the public sector banks, if not, the public sector insurance companies; they are the strength of the Indian economy? I consider that they are the fundamentals if you think of our economy. These fundamentals are being weakened now. In the name of disinvestment, in the name of privatization, selling of Government equities, these fundamentals are being broken. Weakening of public sector weakens our economy, and it fails us to achieve, accomplish the social objectives, the national objectives. What is the social objective and the national objective that should be there? And the Government can have satisfaction quoting Moody's report. But, they also should take note of the world's hunger report, which says, India has got the largest number of malnutrition children.

Our children are malnourished. They do not get food, and they starve; twelve crore of our children are malnourished. What is that we claim that India has grown? India is a power when our children do not get food! They are malnourished, and it puts India below 139 countries, as a country, which has hunger. This is the Hunger Report. I am not blaming one party, this party or that party. What are we doing to work on this problem and save our population? Sir, providing healthcare, providing education, providing decent dwelling, providing adequate means of livelihood, must be the objective of any Government. That is what will decide the state of the economy. And here, I would like to underline one thing. Fundamentals are being broken. This Government started it by breaking the Planning Commission. First, they dismantled the Planning Commission. They formed the NITI Aayog, and I always used to say that NITI Aayog is not a national institution for transforming India; it is a national institution for transferring public institutions to private sector. That is what NITI Aayog is doing, and we oppose the privatization of the public sector. When they talked about privatizing the Railways, we criticized; when they talked about privatizing the Air India, the Airports Authority of India, we opposed. We do not agree with that understanding of the Government, and we opposed the privatization of the

Salem Steel Plant and other public sector undertakings. We opposed the privatization of Ordinance Factories in this country. Now, Sir, this Government has taken a decision even to get rid of the soldiers' uniforms, and they have taken a decision to grant Rs. 10,000 as uniform allowance to the soldiers of the Armed Forces.

(contd. by 3l/skc)

SKC/3L/4.45

SHRI D. RAJA (contd.): It meant that instead of providing stitched uniforms to our soldiers, allowance was given towards the same. This decision would result in closure of five groups of ordinance and equipment factories of which four are located in Uttar Pradesh. Professor Ramgopalji, four factories located in Uttar Pradesh and one factory located in Tamil Nadu would be closed and 12,000 employees, including two per cent women employees, are likely to lose their jobs. On the one side, you are talking about creating jobs; on the other side, you are forcing people to lose their jobs. What is the policy that we are following, Sir? This is where I strongly feel that Government must have a rethink on its policy of disinvestment. Government should not go in for reckless and massive disinvestment of public sector undertakings.

Then, Sir, I wish to make another point that some people have already touched upon. The Planning Commission has gone. Earlier, the Planning Commission used to issue directives for the Scheduled Castes Component Plan and Tribal Sub-Plan. Now, what is happening to the Scheduled Castes Component Plan and Tribal Sub-Plan? How are you allocating money in your Budget for that? We have been demanding that there should be a Central legislation on the Scheduled Castes Component Plan and Tribal Sub-Plan. The previous Government didn't agree to it and what this Government's thinking on that is, nobody knows. Everybody keeps talking about Dr. Ambedkar and social justice, but when it comes to taking action on the ground for the society, nothing is happening. Are we deceiving ourselves? Are we deceiving our people, sitting in Parliament? What is our commitment to social justice? How are we going to do it if we don't address these questions? Sir, these are the working people. I am not talking in terms of Castes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and so on. They are the working class. They create wealth. What is their share in the nation's wealth? What is the share of these working people in the country's wealth? Let the Finance Minister address these questions. How come the corporate houses own the majority of the wealth of this nation?

How does that happen? These are the issues which we need to address. I hope the Finance Minister would give thought as to how the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be taken care of when he prepares the Budget.

Sir, they talked about reservation. Even the last week I spoke on the issue of reservation in the private sector. If there can be reservation in the public sector, why can't it be extended to the private sector? What is private about private sector in the given situation? Private sector takes money from public sector banks. Private sector gets all the concessions from the Government and they claim to be private! What is private about a private sector? We have the definition of 'public sector'. As even Mr. Pranab Mukherjee had said, a 51 per cent Government equity would maintain the public character of any company or factory. Now, what is the definition of 'private sector'? These are some of the issues that this Government needs to address.

Finally, Sir, I come to agriculture. Agriculture is in deep crisis. Farmers are committing suicide. The Government talks about doubling the income of farmers. You are not setting up a farmers' income commission, at least, to study the problems of farmers, and you talk about doubling the

income of farmers! You are not giving farmers the Minimum Support Price for crops. The other day, my friend from Odisha, Mr. Tirkey, raised the issue of providing the MSP for paddy to farmers. Why can't the Government provide the MSP to farmers? Why do you constitute so many commissions? There is the Swaminathan Commission and other commissions. What happened to its report? Why are we not taking up the recommendations made in the Swaminathan Commission Report? Agriculture is a neglected sector. Unless we address the agrarian crisis in an earnest and sincere manner, we cannot retrieve our economy. Our economy is in a deep crisis. We cannot boast and pat ourselves. The economy is in a bad shape. We must admit that fact. From there we will have to move forward, correcting

our policies. There is a need for course correction. There is a need for reviewing the present economic policies pursued by the Government.

Thank you, Sir.

(Ends)

(FOLLOWED BY KSK/3M)

KSK/RPM/4.50/3M

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (KARNATAKA): Sir, as you know, this Government likes to break new records. When it comes to the issue of unemployment, the employment generation in 2015 hit a six-year low; in 2016, it hit a seven-year low; and, in 2017, it hit an eight-year low. So, that is the record of this Government. When you actually look at the India Exclusion Report and the Labour Bureau data, you see that employment generation is negative in a majority of the eight sectors which employ the largest number of Indians - textiles, leather, metals, automobiles, gems and jewellery, transport, IT and handlooms. Only 1.35 lakh jobs were created when more than 1.2 crore people entered the workforce.

Sir, basically, the Government is in denial. Recently, there was a session at World Economic Forum's India Economic Summit and one of the Ministers actually made a statement. When everyone expressed concern

about job losses in the formal sector, he actually said that companies bringing down their employment is a very good sign, in fact. Okay. I quote, "The country today is seeing more and more young people wanting to be entrepreneurs." If that were the case, that would be wonderful. But, look at the state of entrepreneurship under this Government. The MUDRA Scheme, which they like to tom-tom, is supposed to give Rs.10 lakhs in loans to every entrepreneur. Instead, the average loan is Rs.44,000. That is less than the median household income. What kind of jobs are you creating with that?

Sir, another big story is the Startup Mission. The Local Circles Media Platform conducted a survey of 33,000 Startup entrepreneurs. Eighty per cent of them said that they are not benefited from this Mission. When you look at other tax benefits for Startups, you will find that there were exactly 111 firms that have actually benefited and got tax benefits from that particular scheme. Sir, their own Chief Economic Adviser suggested to them that the Government should focus on two key sectors - textiles and leather - because they have huge job creation potential. Instead, what you had was the demonetization devastating the textile sector along with the hasty implementation of GST, and, of course, the cattle slaughter rules, which went ahead in totally disrupting the leather industry overall. So, basically,

construction is also in deep distress. IT is seeing lay-offs. Regarding agriculture, my colleagues have talked enough about the kind of crisis that we are facing. Fundamentally, gross fixed capital formation in the private sector is in deep trouble and at record lows, and the Government is not doing anything about it.

Sir, when you think about where job creation happens, it is in the medium, small and micro enterprises sector, in the informal sector. They have demonetized these sectors and devastated them by saying that these are cash-driven sectors and, therefore, they are all illegal and criminal. That is a very, very wrong move and it is the time for them to change their approach towards these sectors which is where the jobs are actually created. Sir, unfortunately, entrepreneurs have to shut down their businesses and job seekers have become discouraged. Enough number of people are migrated back to their villages and that is why the Finance Minister announced record allocation to MNREGA because people have gone back to take refuge in the social safety net that we established.

Sir, last year, we came out with a report in January called, 'The Real State of the Economy', and we presented that to the nation. We will be presenting one more report this year. But, last year, the title of that report

was, 'Where are the jobs, Mr. Prime Minister?'. Sir, we have not got an answer. The people of India are going to ask this Government that question in 2019 and they will have no answer to that, and that is the real disaster for India and its demographic dividend which is squandering in front of our eyes because they are not paying attention to the jobs and employment issue. I am sorry to say that. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Rajeev Shuklaji, I am sorry. I got your name, but...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, श्री आनन्द शर्मा जी एवं बहुत सारे अन्य माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार विस्तार से प्रकट कर दिए हैं। मुझे सिर्फ दो ही चीजें वित्त मंत्री जी से पूछनी हैं। पहली तो यह कि मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट है कि 6 हजार एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़कर माइग्रेट कर गए हैं , यानी वे बाहर चले गए हैं या बाहर बस गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है ? वे क्यों देश छोड़कर गए हैं? क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हेरेसमेंट की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है?

महोदय, अगर जॉब क्रिएशन होना है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्ज़ नहीं हैं। प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर जॉब दे सकता है। अगर वह रिपोर्ट सच है, तो क्या वजह है कि ये लोग छोड़कर जा रहे हैं?

महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं। अब तो उसे भी चार साल बीत गए हैं। इधर से भी पॉइंट आउट किया गया था और मैं भी पूछना चाहता हूं कि उसका कितना परसेंट कंज्यूमर को पास ऑन किया किया जा रहा है? मैं समझ सकता हूं कि ऑयल कंपनीज़ की हालत खराब है और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पैसा खर्च होगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज कंज्यूमर्स को भी जा रहा है ? यह बात सभी जानते हैं कि तभी प्राइस राइज होता है, यानी महंगाई बढ़ती है, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, डीज़ल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते हैं। उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और प्राइस राइज़ होता है।

(3 एन/पीएसवी पर जारी)

PSV-SK/3N/4.55

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत): उसका सीधा असर महँगाई पर पड़ता है, प्राइस राइज़ पर पड़ता है। तो उस मामले में कंज्यूमर को कितना परसेंटेज जा रहा है, क्योंकि यह जितना कम होगा, उसी हिसाब से वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। तो international prices में यह जो reduction है, इसका कितना परसेंटेज प्राइस राइज रोकने के लिए कंज्यूमर को pass on किया जा रहा है? यही दो बातें मैं पूछना चाहता हूँ, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Hon. Finance Minister.

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली): उपसभापति जी, मैं माननीय श्री आनन्द शर्मा जी का और उन सभी साथियों का आभारी हूँ, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और उसके साथ सम्बन्धित विषयों पर इस चर्चा में भाग लिया है।

स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चर्चा जब संसद में होती है, तो अपने अनुभव के आधार पर जो समस्याएँ सांसदों को, राजनीतिक दलों को समझ में आती हैं और जो जनता का दुख-दर्द और पीड़ा भी समझ में आती है, वह अर्थव्यवस्था की इस बहस के अन्दर अपने आपको प्रकट करती है। इसके साथ-साथ, थोड़ा सा हम सबका, राजनीतिक दलों का भी एक स्वभाव होता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी हर चीज़ को देखें, राजनीतिक चश्मे से हर चीज़ को देखें। अब यह स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अपनी अर्थव्यवस्था में भी, अपनी निर्णय प्रक्रिया में भी, जो सुधार होना चाहिए, वह भी आवश्यक है और अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनाना भी आपके लिए आवश्यक है। पिछले साढ़े तीन-चार सालों में, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, सरकार ने अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में जो निर्णय प्रक्रिया है, वह जनता के हित में हो, अर्थव्यवस्था के हित में हो और उसकी एक विश्वसनीयता बने, इसके लिए अनेकों कदम उठाये हैं। राजनीतिक टिप्पणी की दृष्टि से जब आनन्द शर्मा जी कहते हैं कि बहुत खराब स्थिति है, तो खराब स्थिति-- पूरे विश्व का माहौल क्या है? वे अनुभवी व्यक्ति हैं। वे संसद में बहुत समय से हैं, मुझसे पहले से हैं। वे बहुत सालों तक मंत्री रहे हैं। जब विश्व की अर्थव्यवस्था तेज़ी से चलती है, तो स्वाभाविक है कि सभी देशों को उसका लाभ होता है और जब हम

विकास दर को measure करते हैं, तो उस वक्त पूरी दुनिया की स्थिति क्या थी? जब विश्व में boom period आता है, तेज़ी आती है और उस तेज़ी के दौरान, स्वाभाविक है कि वह 2003 में आरम्भ हुई और भारत को भी उसका लाभ हुआ था, लेकिन बाद में जब चुनौतियाँ आईं, तो सिर्फ एक बार याद कर लीजिए कि क्या स्थिति थी, जिसमें छोड़ कर गये थे।

आज आपने GDP की new series का जिक्र किया, लेकिन जब यह new series लागू हुई, तो यह 2014-15 से लागू नहीं हुई, यह 2011-12 से लागू हुई। आपकी सरकार के भी जो आखिरी तीन साल थे, उसी revised series के हिसाब से-- Revised series के पीछे यह उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था का चरित्र बदला है, उसमें काफी आइटम्स और विषय आये हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था की जो वास्तविकता है, वह उस GDP में रिफ्लेक्ट हो जाये। आपका अनुभव भी आपको बतलायेगा कि अक्सर सरकारें-- मैं मानता हूँ कि आपकी सरकार में भी यह रहा होगा कि जो संस्थाएँ इसको measure करती हैं, CSO वगैरह, सरकार का अंग होती हैं, लेकिन political establishment उससे an arm's distance रखता है। Political establishment को भी अन्तिम समय पर ही पता चलता है कि इस बार का डेटा क्या है।

(3ओ/वीएनके पर जारी)